



हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएसओ :90012015 प्रमाणित कंपनी

**Housing & Urban Development
Corporation Limited**
(A Govt. of India Enterprise)
An ISO 9001:2015 Certified Organisation

सीआईएन L74899DL1970GOI005276:वेबसाइट www.hudco.org.in:

पंजीकृत कार्यालय :हडको भवन ,कोर7 ए ,इंडिया हैबिटेड सेंटर,लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

निविदा आमंत्रण

एक वर्ष की अवधि के लिए इंड-एस परामर्शदाता के रूप में व्यावसायिक
सीए फर्म की नियुक्ति।

अध्याय

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	हडको का परिचय	2
2	बोली के सामान्य नियम एवं शर्तें	3-6
3	कार्यक्षेत्र की संभावनाएं	7- 9
4	तकनीकी बोली के लिए तकनीकी मानदंड एवं प्रारूप	10-12
5	वित्तीय बोली का प्रारूप	13

अध्याय:1 हडको का परिचय

1.1 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हडको, भारत सरकार (जीओआई) के स्वामित्व वाली प्रमुख तकनीकी-वित्तीय संस्था है, यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। हडको की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी तथा इसे भारत में आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। हमें भारत सरकार द्वारा मिनी रत्ना (श्रेणी-1 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) का दर्जा प्राप्त है। हमारे आवासीय वित्तीय ऋण सामाजिक आवास, आवासीय रियल एस्टेट और खुदरा वित्त के रूप में वर्गीकृत हैं जो हडको निवास (समेकित आवासीय वित्त) के नाम से जाने जाते हैं। हम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त के संबंध में निम्नलिखित परियोजनाओं से संबंधित ऋण सेवाएं प्रदान करते हैं :

- जलापूर्ति;
- सड़कें एवं परिवहन ; बिजली ;
- नए उभरते क्षेत्र जैसे सेज़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र), औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइप लाइन, तेल टर्मिनल तथा दूरसंचार क्षेत्र परियोजनाएं;
- व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य, जिनमें बिक्री केंद्र, बाज़ार परिसर, मॉल-कम-मल्टी प्लेक्स, होटल तथा कार्यालयी इमारतें आती हैं;
- सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा क्षेत्र विकास; तथा
- सीवरेज, ड्रेनेज तथा ठोस कचरा प्रबंधन (समेकित रूप में “शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त”)

1.2 वित्तीय प्रचालनों के अलावा हडको शहरी और क्षेत्रीय योजना, डिजाइन और डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सामाजिक विकास, सरकारी कार्यक्रम एवं अन्य, शोध और अध्ययन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय भवन निर्माण सामग्री, किफायती और नवीनतम निर्माण कार्य तकनीकों के क्षेत्र में भी परामर्श सेवाएं आमंत्रित करता है। कंपनी, उसके राष्ट्रव्यापी स्तर पर फैले हुए क्षेत्रीय और विकास कार्यालयों में स्थापित एक मजबूत और बहु-अनुशासनात्मक कार्य बल के माध्यम से कार्य करती है। हडको मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हडको की आय के स्रोत में ऋण पर ब्याज , प्रक्रिया शुल्क ,परामर्श सेवाएं ,मंत्रालय की ओर से हडको द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं और मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं, किराया सेवाएं ,निर्माण कार्य संबंधी सेवाएं , वास्तु शिल्पीय सेवाएं आदि शामिल हैं।

वर्तमान में हडको एचएनबी के साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत है। भारत सरकार ने 9 अगस्त ,2019 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से आरबीआई को एचएफसी के लिए नियामक बना दिया था और देखरेख का कार्य एनएचबी के पास बना रहा। आरबीआई ने एचएफसी के लिए नियामक ढांचे पर 22 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना जारी की है । हडको ने एचएफसी से एनबीएफसी-आईएफसी में बदलने के लिए 29 मार्च, 2022 को आरबीआई को आवेदन प्रस्तुत किया है। आरबीआई ने अपने 8 अप्रैल, 2022 के पत्र के माध्यम से हडको से विशिष्ट विवरण और जानकारी मांगी। प्रबंधन को वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई से उक्त अनुमोदन प्राप्त होने का अनुमान लगाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हडको आरबीआई के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया में है। अधिक जानकारी के लिए बोलीकर्ता हडको की वेबसाइट www.hudco.org.in .in का संदर्भ कर सकते हैं।

अध्याय :2 बोली के सामान्य नियम एवं शर्तें

- 2.1 कंपनी का प्रयोजन इंड-एएस में व्यावसायिक सेवाओं के लिए एक परामर्शदाता को सेवाप्रदाता आधार पर नियुक्त करना है। इंड-एएस में सेवाप्रदाता आधार पर व्यावसायिक सेवाओं के लिए योग्य सीए फर्म द्वारा बोली लगाने के लिए यह आमंत्रण जारी किया गया है।
- 2.2 कम्पनी, बोली सम्बन्धी दस्तावेज़ के भाग 3 में उल्लिखित कार्यक्षेत्र की सम्भावनाओं के विषय में इंड-एएस परामर्शदाता नियुक्त करने की इच्छुक है।
- 2.3 जिन व्यावसायिक संस्थान/संस्थानों को वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए हडको लिमिटेड के लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है, वह संस्थान इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
- 2.4 शुरुआत में सीए फर्म, नियुक्ति तिथि से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त की जाएगी। हालांकि, हडको के स्व विवेक पर फीस सहित पूर्व नियमों एवं शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन होने पर इसे वार्षिक आधार पर दो वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- 2.5 बोली लगाने की प्रक्रिया के प्रबंध और परिणाम, यदि कोई हो तो, पर ध्यान दिए बगैर प्रस्ताव तैयार करने से जुड़ी पूरी लागत के लिए बोलीकर्ता उत्तरदायी होगा।
- 2.6 निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में हडको का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।
- 2.7 बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा आमंत्रण में दी गई निर्धारित तिथि और समय से पूर्व ही निविदा निर्देशित स्थान पर पहुँच जाए। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदा सहित देरी से प्राप्त हुई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अगर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा खुलने के दिन अवकाश है तो ऐसी स्थिति में बोली प्राप्त होने की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए अवकाश से अगले कार्य दिवस पर बोली को खोला जायेगा।
- 2.8 बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव तकनीकी बोली खुलने के 60 दिनों की अवधि तक ही स्वीकृति के लिए मान्य होगा। अपवादात्मक परिस्थितियों में यदि मूल बोली अवधि की वैधता समाप्त होने से पूर्व, बोलीकर्ता के लिए बोली की वैधता को एक निर्दिष्ट अवधि बढ़ाना हडको के लिए अपेक्षित होगा।
- 2.9 यह दस्तावेज़/आमंत्रण अहस्तांतरणीय है। आमंत्रण तथा इसके नियमों के अनुसार दी जाने वाली सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से गोपनीय हैं तथा आवेदनकर्ता के अतिरिक्त, हडको की लिखित सहमति के बिना अन्य किसी व्यक्ति के सामने इसे नहीं खोला जा सकता है।

2.10 बोली 17 नवंबर, 2022 अपराहन 4 बजे तक जमा की जा सकती हैं। 17 नवंबर 2022, 4 बजे के बाद जमा की गई बोलियों के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कम्पनी किसी भी आवेदनकर्ता के आवेदन प्राप्त होने की जवाबदेह नहीं होगी। हालाँकि, तकनीकी बोली के मूल्यांकन की अंतिम तिथि के बाद कम्पनी अपने सम्पूर्ण अधिकार के आधार पर आवेदनकर्ताओं से किसी अतिरिक्त जानकारी, सामग्री या साक्ष्य की मांग कर सकती है।

2.11 हडको, बोली जमा करने की निर्धारित समय सीमा से पहले किसी भी समय परिशिष्ट जारी कर किसी भी कारणवश बोली दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है।

2.12 एक बोलीकर्ता पूरे कार्यक्षेत्र के लिए एक ही बोली प्रस्तुत करेगा। इस नोटिस में इंगित व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आंशिक कार्य/टाई अप व्यवस्था की अनुमति नहीं है। वित्तीय बोली को भागों में विभाजित करने की अनुमति नहीं है।

2.13 अनुमानित लागत अर्थात ₹9600/- पर 2% की गैर -ब्याज धारक ईएमडी (जमा बयाना राशि) का भुगतान हडको को केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
ब्रांच का नाम एवं पता	बी-3-4, सूर्य किरण बिल्डिंग 19, के जी मार्ग, नई दिल्ली
लाभार्थी का नाम	हडको लिमिटेड
खाता संख्या	00030350017801
आईएफएससी	एचडीएफसी0000003

ईएमडी ऊपर बताए गए माध्यम के अलावा किसी अन्य तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थानों को ईएमडी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। ईएमडी से छूट प्राप्त करने के समर्थन में उन्हें अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भौतिक रूप में या फिर किसी अन्य माध्यम द्वारा जमा की गयी ईएमडी अमान्य होगी। ईएमडी के साथ कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं जुड़ेगा।

2.14 हडको के पास कार्य सौंपने से पूर्व ही किसी भी समय इंड-एएस परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

2.15 आवेदनकर्ता तकनीकी बोली की तकनीकी व्यवहार्यता के मानदंड को पूरा करने के समर्थन में,

अध्याय 4 के अनुसार दस्तावेजों के पूरे सेट को एक सीलबंद लिफाफे में जमा करेंगे, लिफाफे पर **“भाग- I इंड-एस परामर्शदाता के लिए तकनीकी बोली”** लिखना अनिवार्य होगा।

2.16 आवेदनकर्ता अपनी वित्तीय बोली के समर्थन में **अध्याय 5 के अनुसार** अपना आवेदन मदवार एक अलग सीलबंद लिफाफे में जमा करेंगे जिस पर **“भाग- II इंड-एस परामर्शदाता के लिए वित्तीय बोली”** लिखा होना चाहिए।

2.17 उपरोक्तानुसार दोनों ही लिफाफे एक अलग मुहरबंद लिफाफे में होने चाहिए । उस मुहरबंद लिफाफे पर संस्थान के नाम और पते के साथ **“इंड-एस परामर्शदाता के लिए बोली”** विधिवत रूप से लिखा गया हो। यह बोलियां सामान्य लेखा विभाग, हडको मुख्यालय (कोर7ए, हडको भवन, इंडिया हैबिटैट सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003) द्वारा ऐसी विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित सीए फर्म से आमंत्रित की गयी हैं जो इंड-एस परामर्श सेवाएं दे रही हो और उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर इंड-एस के क्षेत्र में व्यावसायिक परामर्श सेवाएं देने के अनुकूल हो। बोली कम्पनी के उपरोक्त उल्लिखित पते पर पांचवी मंजिल में निर्धारित निविदा बॉक्स में ही जमा की जाएगी।

2.18 यदि फर्म बोली लगाने की अंतिम तिथि से पहले अपनी बोली में संशोधन करना चाहती हो तो लिफाफों पर स्पष्ट रूप से **“इंड-एस परामर्शदाता के लिए संशोधित बोली”** लिखा होना चाहिए । इसके साथ ही संशोधित बोली में सभी दस्तावेजों को संलग्न किया गया हो और यह भी लिखा होना चाहिए कि फर्म ने अपनी स्वेच्छा से मूल बोली को वापस लिया है। ऐसी स्थिति में मूल बोली को नहीं खोला जाएगा।

2.19 जिन आवेदनकर्ताओं को कार्य नहीं सौंपा जाएगा वह सभी अपने ना चुने जाने का कारण नहीं पूछ सकते । यदि इस मामले में कंपनी पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगता है/ आवेदकों के किसी भी कार्य से कम्पनी की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचती है तो कम्पनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कानूनी तरीके से उस नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट में दावा कर सकती है ।

2.20 फर्म को (“आवेदक” के रूप में संदर्भित) **“तकनीकी व्यवहार्यता”** के पालन के लिए सभी तकनीकी मानदंड (अध्याय-4) पूरे करने होंगे ।

2.21 फर्म के (आवेदक के रूप में संदर्भित) **“वित्तीय बोली”** के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य हो ।

2.22 बोलीकर्ता केवल (अध्याय-5 में उल्लिखित) निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही फीस उद्धृत करेगा ।

बोलीकर्ता कीमत बोली में बिना किसी काट छांट के शब्दों और संख्या दोनों रूप में बोली उद्धरित करेगा। बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत की गयी कीमतें निश्चित, स्थिर एवं तिमाही आधार पर लागू होंगी (लागू कर अलग से इंगित किए जाएंगे)।

- 2.23 अनुमानित वित्तीय बोली **प्रत्येक तिमाही (अधिकतम सीमा)** ₹1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) कर सहित है।
- 2.24 हडको को यह अधिकार है कि किसी फर्म के संतोषजनक सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर उसके उल्लिखित पते पर नोटिस भेजकर कॉन्ट्रैक्ट को तत्काल समाप्त कर सकता है। इंड-एएस परामर्शदाता (सीए फर्म) द्वारा सेवाओं में किसी भी प्रकार के असन्तोषजनक प्रदर्शन/विलम्ब/क्षति होने पर हडको का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। ऐसी स्थिति में हडको कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिपूर्ति किए बगैर बिना किसी सूचना के सीए फर्म से क्षतिपूर्ति कर सकता है।
- 2.25 शुल्क सीए फर्म के कामकाज की तिमाही रिपोर्ट (बिन्दुवार) में संलग्न इनवॉइस के आधार पर तिमाही शुल्क के रूप में जारी होगा। जिसमें से हर तिमाही फीस का 20% हडको द्वारा बिना किसी ब्याज के प्रतिभूति जमा के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा, जिसे एक वर्ष की अवधि के बाद तथा कार्य में संतोषजनक प्रदर्शन होने पर संस्थान को जारी कर दिया जाएगा।
- 2.26 यदि आवेदक तकनीकी व्यवहार्यता को पूरा नहीं कर पाता, तो भाग-II को नहीं खोला जाएगा और उसे वैसे ही रद्द कर दिया जाएगा। कम्पनी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह आवेदन रद्द किए जाने की सूचना आवेदनकर्ता फर्म को भेजे।
- 2.27 आवेदनकर्ता का चयन पूरी तरह से कम्पनी के निर्णय पर निर्भर है। चयन का आधार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी योग्य और या न्यूनतम बोली होगी। यदि किन्हीं दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी न्यूनतम बोली के बीच टाई हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसी संस्थान को वरीयता दी जाएगी जिसके इंड-एएस के पीएसयू ग्राहकों की संख्या अधिक हो।
- 2.28 बोलीकर्ता द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने पर हडको उनकी बोली को रद्द कर सकता है।
- 2.29 इंड-एएस परामर्शदाता की नियुक्ति एक माह की पूर्वसूचना देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- 2.30 इस पर विशेष ध्यान दें कि इंड-एएस के अतिरिक्त आंतरिक लेखा परीक्षा, कर लेखापरीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा या किसी अन्य कार्य से संबंधित दस्तावेजों को बोली के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय :3 कार्यक्षेत्र की संभावनाएं - इंड-एएस परामर्शदाता

एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यक्षेत्र की संभावनाओं में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे । निम्न सूची सांकेतिक है सम्पूर्ण नहीं :

1. कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान इंड-एएस/कंपनी अधिनियमों का अनुपालन करते हुए तिमाही/ अर्द्धवार्षिक / वार्षिक (एकल एवं समेकित) खाते तैयार करने में सहायता करना ।
2. इंड-एएस अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता करना । खातों एवं उनके लेखा परीक्षा तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों और सीएजी लेखा परीक्षकों से नोट सहित उसपर टिप्पणी करना ।
3. सांविधिक विनियमों तथा नीतियों के इनपुट एवं समीक्षा सहित इंड-एएस की लेखांकन नीतियों एवं प्रक्रियाओं (एकल एवं समेकित) का निर्धारण करने में सहायता करना ।
4. कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान इंड-एएस अनुरूप लेखापरीक्षा के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों और सीएजी कार्यालय के प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करना।
5. उपरोक्तानुसार इंड-एएस अनुरूप खातों को तैयार करने के उद्देश्य से अपेक्षित कर निर्धारण की गणना से सम्बंधित कार्यों तथा कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक मामलों में सहायता देना ।
6. कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में उपयुक्त वित्तीय विवरण सम्बंधित रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया / कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय / राष्ट्रीय आवास बैंक / इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया / सेबी एवं अन्य किसी नियामक निकाय द्वारा इंड-एएस में प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन / संशोधन को समय से संयोजित करवाने में सहायता करना और उन बदलावों को व्यावहारिक रूप में लाने की दिशा में कार्य करना ।
7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि खाते तैयार करने से जुड़े विषयों पर वैचारिक मतभेद या फिर कंपनी की स्थिति को स्पष्ट करने तथा पद्धति/प्रक्रिया में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता/ अपेक्षा होने पर लेखा परीक्षकों / वैधानिक लेखा परीक्षकों / सरकारी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा के लिए परामर्शदाता को हडको के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा ।
8. परामर्शदाता फर्म को हडको के वित्तीय विवरणों पर लागू होने वाले किसी भी परिवर्तन/संशोधन पर

अपने विचार लिखित रूप में हडको को प्रस्तुत करने होंगे।

9. इंड-एएस से सम्बन्धित गणना तथा उनके रिपोर्टिंग निर्देश एवं डिसक्लोज़र चेक लिस्ट बनाने में परामर्शदाता अन्य विभागों को सहयोग/सहायता करेगा ।
10. ईआरपी हडको कार्यान्वयन के अंतर्गत आता है इसलिए परामर्शदाता को आईटी पद्धति और प्रक्रिया में जहां भी आवश्यक हो परिवर्तनों की पहचान करने में सहायता करनी होगी । परामर्शदाता इंड-एएस कार्यान्वयन के लिए मौजूदा लेखाविधि प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों को लाने में हडको के आईटी विभाग को सुविधा प्रदान करने में सहयोग एवं सहायता करेगा।
11. हडको के अधिकारियों को कम से कम दो प्रशिक्षण (प्रत्येक प्रशिक्षण के दो दिन) लेने होंगे, यह प्रशिक्षण इंड-एएस के अवलोकन एवं उसमें हुए परिवर्तनों, विशेष रूप से हडको के लिए लागू होने वाले इंड-एएस के वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने से जुड़े विषयों और उसमें हुए नवीनतम परिवर्तनों को लेकर होगा । आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की संख्या में वृद्धि की जा सकती है ।
12. परामर्शदाता नियमित आधार पर इंड-एएस का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले स्टाफ की टीम नियुक्त करेगा जो त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक /वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में (हडको की आवश्यकता और सूचना के आधार पर) सहयोग करेगा । इसके अलावा इंड-एएस का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट/ कोस्ट मेनेजमेंट अकाउन्टेन्ट को सामान्य कार्य दिवसों में कम से कम एक दिन उक्त कार्य के लिए हडको में उपस्थित रहना आवश्यक होगा ।
13. हडको प्रबंधन द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने / अंतिम रूप देने के लिए इंड-एएस से सम्बन्धित कोई अन्य सेवाएं / सहायता देना।
14. इंड-एएस परामर्शदाता संस्थान एक ऐसे सहभागी की प्रतिनियुक्ति करेगा जो उक्त विषय का जानकार हो और सम्बन्धित परामर्श कार्यों के लिए कम से कम एक बार या जब भी आवश्यक हो, हडको मुख्यालय में उपस्थित हो सके। उपरोक्त प्रतिनिधि को इंड-एएस के मामलों में हडको की आवश्यकतानुसार , उसे मुख्यालय के सामान्य लेखा विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित रहना होगा ।
15. इंड-एएस परामर्शदाता कॉन्ट्रैक्ट के कार्यकाल या उसके बाद तक भी कामकाज से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखेगा, केवल हडको से लिखित अनुमति के बाद ही उक्त कार्य की जानकारी या उसके परिणामों को किसी अन्य के साथ साझा किया जा सकता है । इंड-एएस परामर्शदाता इस ओर भी सतर्क रहेगा कि किसी अन्य परामर्शदाता, एजेंट या उनके कार्मिक उन गोपनीय सूचनाओं को ना फैलाएं । यदि किसी भी प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो किसी भी आर्थिक नुकसान/ क्षति की पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी ।

16. इंड-एएस परामर्शदाता कार्यक्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उनके निष्पादन के लिए हडको की आवश्यकतानुसार योग्य व्यावसायिकों की एक टीम बनाएगा। इंड-एएस परामर्शदाता टीम सदस्यों के सभी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से स्वयं ही उत्तरदायी होगा। नियुक्त किए गए व्यावसायिकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने, स्वीकृति/ दस्तावेज़ लेने तथा हडको की आवश्यकतानुसार उन्हें अपनी अपनी परामर्श सेवाएं देने के लिए नियमित अन्तराल पर हडको में उपस्थित रहना होगा ।
17. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, इंड-एएस सलाहकार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर कंपनी/लेखा परीक्षकों के लिए उपयुक्त प्रारूप में उस रिपोर्टिंग अवधि की सीमित समीक्षा रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।
18. कार्य को पूरा या रद्द किए जाने पर इंड-एएस परामर्शदाता के पास मौजूद सभी आंकड़े, जानकारी, सामग्री, रिकॉर्ड, दस्तावेजों की प्रति या अन्य सम्बंधित कागज़ात पूर्ण रूप से सिर्फ हडको की संपत्ति होगी तथा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर इन सभी को हडको को वापिस किया जाना अनिवार्य होगा ।

अध्याय :4 बोली जमा करने का तकनीकी मानदंड और प्रारूप

क्र.सं.	शर्तें	आवश्यक दस्तावेज़	अनुलग्नक संख्या
1.	फर्म के पते का वैध प्रमाण। फर्म का मुख्यालय एनसीआर में होना चाहिए।	फर्म का आईसीएआई वेबसाइट से प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ।	अनुलग्नक- 1
2.	सीए फर्म के पास निविदा जमा करने की तिथि तक कम से कम पांच सहयोगी होने चाहिए।		
3.	निविदा तिथि तक संस्था के पास वेतन पर रखे हुए सीए कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए (साझेदार और सहायकों को छोड़कर)।		
4.	फर्म के कम से कम 3 सहभागियों के पास सीए के रूप में कार्य करने का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो ।		
5.	बोलीकर्ता संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए सभी योग्य व्यवसायिकों (सहभागी और वेतन पर रखे गए सीए कर्मचारी) का संक्षिप्त विवरण तथा हडको द्वारा सौंपे गए कार्यों एवं कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सदस्यों का विवरण जैसे नाम, अनुभव, प्रोफाइल ,विशेषज्ञता आदि ।	फर्म के लेटर हेड पर पूरा विवरण और आईसीएआई सहयोगी का सदस्य कार्ड ।	अनुलग्नक- 2
6.	जीएसटी संख्या	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र	अनुलग्नक- 3
7.	सीए फर्म के पास पीएसयू की इंड-एएस परामर्श सेवाएं देने का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव हो, जिसमें से एनबीएफसी में इंड-एएस परामर्श सेवाओं का दो वर्ष का अनुभव हो ।	संतोषजनक पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेश की प्रति संलग्न हो।	अनुलग्नक- 4
8.	बोलीकर्ता यह घोषित करेगा कि क्या उसकी	फर्म के लेटर हेड पर प्रमाण पत्र	अनुलग्नक- 5

	फर्म/कम्पनी का हडको में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी से कोई संबंध है, तथा, यदि है तो उस कर्मचारी का नाम और उसका सम्बन्ध हडको के निदेशकों में से किसी के साथ या क्या किसी का भी सम्बन्ध नए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) के तहत या सांविधिक लेखा परीक्षकों (मैसर्स एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी) के साथ तथा हडको के साथ आंतरिक लेखा परीक्षक (मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी) के साथ है, यदि हां, तो विवरण दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की वह नए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 184 और 188 के अनुपालन में है।		
9.	उन कार्यों की सूची जो हडको मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय पर किये जा रहे हैं।	कार्य-आदेश की प्रति संलग्न हो।	अनुलग्नक- 6
10.	उपरोक्त के अतिरिक्त, बोलीकर्ता में निम्न में से कोई भी अयोग्यता ना हो :- क. पिछले पांच वर्षों में फर्म के विरुद्ध आईसीएआई या अन्य किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी हो। ख. कोई भी सहभागी/ कर्मचारी किसी भी अपराध/आर्थिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो। ग. भारत के किसी भी कोर्ट में अभ्यास जारी रखने के अधिकार के संदर्भ में कोई भी अपील/ अनसुलझा विवाद/मुकदमा/ मामला लम्बित लम्बित ना हो।	फर्म के लेटर हेड पर इसकी घोषणा।	अनुलग्नक- 7
11.	संस्थान का पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार ₹2 करोड़ होना चाहिए।	वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट।	अनुलग्नक- 8

12.	ईएमडी विवरण।	(i) यू टी आर संख्या और दिनांक (ii) बैंक का नाम (iii) राशि या एमएसएमई प्रमाणपत्र	अनुलग्नक-9
13.	इंड- एस परामर्शदाता को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि वह ना तो स्वयं या ना ही हडको में काम कर रहे किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने देगा और साथ ही वह किसी भी धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में पता चलते ही उसके विषय में यथाशीघ्र हडको को अवगत कराएगा ।	फर्म के लेटर हेड पर प्रमाण पत्र।	अनुलग्नक- 10

टिप्पणी :- सभी निविदा दस्तावेजों पर फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। इस पर विशेष ध्यान दें कि इंड-एस के अतिरिक्त आंतरिक लेखा परीक्षा, कर लेखापरीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा या किसी अन्य कार्य से संबंधित दस्तावेजों को बोली के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर

अध्याय:5 वित्तीय बोली का प्रारूप

वित्तीय प्रस्ताव का फॉर्मेट (फीस शब्दों और अंकों दोनों में उद्धृत होगी)

विवरण	राशि (रु)
कार्यक्षेत्र की संभावनाओं में उल्लिखित दी जा रही सेवाओं के लिए लगभग त्रैमासिक व्यावसायिक शुल्क (लागू कर को छोड़कर)	
जीएसटी (18 %)	
कुल	
राशि शब्दों में- :	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर



**Housing & Urban Development
Corporation Limited**
(A Govt. of India Enterprise)
An ISO 9001:2015 Certified Organisation

CIN: L74899DL1970GOI005276 Website: www.hudco.org.in
REGISTERED OFFICE: HUDCO BHAWAN, CORE 7A, INDIA HABITAT CENTRE,
LODHI ROAD, NEW DELHI -110003

INVITATION OF BIDS

**Appointment of Professional CA Firm as
IND-AS Consultant for a period of one year.**

CHAPTERS

S. No	Chapter	Page No.
1	Introduction about HUDCO	15
2	General Terms & Conditions of Bid	16-18
3	Scope of Work	19-21
4	Technical Criteria & Format for technical Bid	21-22
5	Format for Financial Bid	23

CHAPTER 1: INTRODUCTION ABOUT HUDCO

- 1.1 Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), a premier techno-financial institution owned by Government of India (GOI), is under the administrative control of Ministry of Housing and Urban Affairs. HUDCO was set up in 1970 and mandated with the task of providing loans for housing and urban infrastructure projects in India. We have been conferred the status of Mini Ratna (Category-I Public Sector Enterprise) by the Government of India.

We classify our housing finance loans into social housing, residential real estate and retail finance, which is branded as HUDCO Niwas (collectively, Housing Finance).

With respect to urban infrastructure finance, we provide loans for projects relating to:

- Water supply;
- Roads and transport; Power;
- Emerging sectors, which includes SEZs (special economic zones), industrial infrastructure, gas pipelines, oil terminals and telecom sector projects;
- Commercial infrastructure and others, which includes shopping centres, market complexes, malls-cum-multiplexes, hotels and office buildings;
- Social infrastructure and area development; and
- Sewerage, drainage and solid waste management (collectively, “Urban Infrastructure Finance”).

- 1.2 Apart from the financial operations, HUDCO offers consultancy services in the field of urban and regional planning, design and development, environmental engineering, social development, Government programmes and others, promotes research and studies and help propagate use of local building materials, cost-effective and innovative construction technologies. The company operates through a strong and multi-disciplinary work force placed over its nationwide network of Regional and Development offices. HUDCO Corporate Office is located at New Delhi.

HUDCO's income consists of interest on Loans, processing charges, consultancy services, projects taken by HUDCO on behalf of Ministry and funded by Ministry, rental services, construction related services, architectural services etc.

Presently HUDCO is registered as Housing Finance Company with HNB. The Govt. of India through its Notification dated 9th August, 2019 had made RBI as the regulator for HFCs and the supervision part continued to remain with NHB. RBI has come out with notification dated 22nd October, 2020, on regulatory framework for HFCs. HUDCO has submitted application to RBI on 29th March, 2022 to convert from HFC to NBFC-IFC. The RBI vide its letter dated 8th April, 2022 called for specific details and information from HUDCO. The management reckons to receive the said approval from RBI in FY 2022-23. Till such time, HUDCO continues to retain the status of HFC.

In view of the above, HUDCO is in the process of registration as NBFC-IFC with RBI.

For further details bidders can see HUDCO's website i.e., www.hudco.org.in

CHAPTER 2: GENERAL TERMS & CONDITIONS OF BID

- 2.1 The Company intends to engage a consultant for professional services in Ind AS on retainership basis. This invitation is issued to invite Bids from eligible CA firms for professional services in IndAS on retainership basis. This document is neither a recommendation, nor offer or invitation to enter into a contract, agreement or any other arrangement in respect of the services.
- 2.2 The Company intends to engage Ind AS consultant for the work defined in scope of work as defined in **Chapter 3** of the bidding document.
- 2.3 The firm/ firms have assignment of audit from/of HUDCO Ltd. during FY 2022-2023 are not eligible to participate in this tender.
- 2.4 The CA Firm will be appointed initially for a period of one year starting from the date of appointment. However, at HUDCO's discretion, the appointment may be renewed for subsequent two years on annual basis based on the satisfactory performance on the same terms & conditions including fees.
- 2.5 The bidder shall be responsible for all costs associated with the preparation of this proposal, if any, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.
- 2.6 In case of any dispute, whatsoever, in connection with the invitation, decision of HUDCO shall be final and binding.
- 2.7 Bidders should ensure that bid is delivered before scheduled date, time and place as per instructions given in this invitation. Late bids, including postal delay, will be outrightly rejected. If the last date of submission and opening of the bid happens to be a holiday, the bid shall be opened on the next working day, keeping the last day of receipt of the bidding as the same.
- 2.8 The proposal submitted by the bidder should be valid for acceptance for a period of 60 days from the opening of Technical Bid. In exceptional circumstances prior to expiry of original bid validity period, HUDCO may require the bidder to extend the period of validity for a specified additional period.
- 2.9 This document/invitation is not transferable. The invitations and all communications pursuant to its terms are confidential and are not to be disclosed to any person other than the addressee without prior written consent of HUDCO.
- 2.10 The bids can be submitted till **04:00 PM of 17th November, 2022**. Bids submitted after 04.00PM of **17th November-2022** will not be considered for evaluation. The company will not entertain any communication by the applicants received after the last date of submission. However, the company may, in its absolute discretion, seek additional information or material or evidence from applicant after the last date for evaluation of technical bid.
- 2.11 At any time prior to the deadline for submission of bids, HUDCO may, for any reason, modify the bidding document by issuing addendum.

- 2.12 A bidder shall submit only one bid for entire scope of work. Assigning part of work/tie up arrangement for providing professional services indicated in this notice is strictly not allowed. Splitting the financial bid into parts is not allowed.
- 2.13 Non-Interest bearing EMD (Earnest Money Deposit) of 2% on the estimated cost (i.e. Rs. 9600/-) shall be paid to HUDCO through online mode only, details of which are as under:

Name of the Bank	HDFC Bank Ltd.
Branch Name & Address	B-3-4, Suryakiran Building 19, KGMarg, New Delhi
Beneficiary Name	HUDCO Ltd.
Account No	00030350017801
IFSC	HDFC0000003

EMD shall not be accepted in any other mode except as stated above. However, MSME Firms would be exempted from payment of EMD. In support of their exemption from payment of EMD, the MSME bidder would be required to submit copy of their registration certificate. Further, submission of EMD in physical/ any other mode shall lead to disqualification. EMD shall not carry any interest.

- 2.14 HUDCO reserves the right to cancel the process of appointment of Ind AS consultant at any point of time before the award of work.
- 2.15 In support of fulfilling Technical Feasibility criteria, the applicants shall be required to submit entire set of documents **as per chapter 4** in a sealed envelope, super scribing - **"PART- I Technical bid for Ind-AS Consultant"**.
- 2.16 The applicants in support of their Financial Bid shall be required to furnish their offer **as per Chapter 5** in a separate sealed envelope, super scribing **"PART-II Financial Bid for Ind-AS Consultant"**.
- 2.17 Both the envelope as mentioned above shall be submitted in one main sealed envelope duly marked as **"Bid for Ind-AS Consultant"** and also mentioning the name and address of the firm on the envelopes. The bids are invited by GENERAL ACCOUNTS DEPARTMENT, HUDCO at Head Office (Core 7A, HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi- 110003) from bona-fide & reputed professional firms of Chartered Accountants engaged in the field of Ind AS consultancy having adequate infrastructure and establishment, for rendering professional consultancy services in the field of Ind AS. The bid should be put in the designated tender box kept at the Fifth Floor at the above-mentioned address of the company.
- 2.18 In case the firm wants to revise its bid before the bid closing date then the envelopes should be clearly marked as **"REVISED BID for Ind-AS Consultant"**. In the revised bid all the documents shall be enclosed and also undertaking that the firm has voluntarily withdrawn its original bid. In this case, the original bid will not be opened.
- 2.19 The applicants not being allotted with the assignments shall not solicit any reason for not being so selected. In case, the company finds any allegation / loss of

reputation for the act of the applicants, the company reserves the right to file legal suit in the court law to claim for the damages.

- 2.20 The Firm (referred as “applicant”) should meet the technical criteria(Chapter no. 4) to come under the purview of “Technical Feasibility”.
- 2.21 The Firm (referred as “applicant”) should be Technically Eligible to be considered for evaluation of “Financial Bid”.
- 2.22 The bidder shall quote fees only as per the prescribed format (As per Chapter-5). In the price bid, the bidder shall quote both in words and figures without any correction or overwriting. The prices quoted by the bidder shall remain firm, fixed and on quarterly basis (Applicable taxes to be indicated separately).
- 2.23 The estimated price bid is ₹ 1,20,000/-(Rupees One Lakh Twenty Thousand only) including taxes for **each quarter (maximum limit)**.
- 2.24 HUDCO shall have the right to terminate the contract forthwith by giving notice at the address mentioned herein on failure to provide satisfactory service. The decision of HUDCO regarding dissatisfaction of services/delay/damages caused by Ind-AS Consultant (CA Firm) shall be final. Further in such an event, HUDCO shall have the right to forfeit the compensation for the contract and also recover damages without any further notice to CA Firm.
- 2.25 The fees shall be released on quarterly basis on receipt of the quarterly report of work done (Pointwise) along with Invoice from the CA Firm. 20% of the fees of each quarter will be retained by HUDCO without any interest as security deposit and shall be released after completion of one year and satisfactory completion of work.
- 2.26 In case the applicant does not satisfy the technical feasibility, Part-II shall not be opened and shall be rejected as it is. There will be no obligation on part of the company to send any intimation to the applicant firm in case of rejection of their application.
- 2.27 The selection shall be done based on eligible and/or lowest bid, as the case may be, offered by the applicants subject to the decision of the company. If there is tie in lowest fees between two or more bidder then preference will be given to the firm who has a greater number of PSU clientele of IND-AS.
- 2.28 Incomplete information provided by the bidder shall tantamount to the rejection of bid by HUDCO.
- 2.29 Appointment of Ind AS Consultant may be terminated at any time by giving one-month notice.
- 2.30 It should be noted that documents related to Internal audit, tax audit, stock audit or any other assignment which are other than IND-AS consultancy not required to be submit with bid.

CHAPTER 3: SCOPE OF WORK – Ind AS Consultant

**The scope of services for a period of 1 year would include the following works.
The list below is indicative not exhaustive:**

1. Assisting in Preparation of IND-AS/companies Acts compliant quarterly/half yearly/ yearly accounts (Standalone & Consolidated) falling during the tenure of contract.
2. Assisting in Preparation of IND-AS compliant financial statements and comment thereon including Notes to Accounts and its Audit from the Statutory Auditors and CAG auditors.
3. Assisting in Finalizing Ind AS accounting policies and procedures (Standalone & Consolidated) including Inputs & review of policies and statutory regulations.
4. Assisting in replying to the queries of the Office of Statutory Auditors and CAG during the audit of IND-AS compliant financial statements which are falling during the tenure of contract.
5. Assist in computation of matters relating to taxation required for the purpose of preparation of Ind AS compliant accounts as mentioned above, and matters incidental thereto arising from companies Act, 2013 or any other legislation.
6. Assisting in timely incorporation of any changes/amendments proposed in IND-AS by the Reserve Bank of India/ Ministry of Corporate Affairs/ National Housing Bank / Institute of Chartered Accountants of India / SEBI & Other Regulatory bodies and develop approach to address those changes, if applicable in the financial statements prepared during the tenure of the contract.
7. The consultant shall be required to be available physically in HUDCO's office for discussion on matters arising due to preparation of accounts as mentioned above, with the internal auditors/ statutory auditors/ Government auditors in case of difference of opinion or to clarify the position of the Company and effecting changes in system/ process, in case of need/ requirements.
8. The consultant firm has to submit their opinion on any change/amendment applicable on financial statements of HUDCO in writing to HUDCO.
9. The consultant will assist/help the other departments in Ind AS related computations and in developing reporting instructions and disclosure checklists.
10. As ERP is under implementation in HUDCO, the consultant shall help in identify changes to IT System and processes where required. The consultant will assist/provide inputs to HUDCO regarding changes required in the present accounting system for implementation of IND-AS to facilitate HUDCO's IT department.

11. Trainings to the officials of HUDCO minimum two number of trainings (2 days of each training) on IND-AS covering overview of IND-AS, changes in the Ind AS including latest developments and such aspects about Financial Statement preparation work in accordance with IND-AS applicable to HUDCO. The number of trainings may increase on the actual requirement.
12. The consultant will assist HUDCO by deploying a team of staff who has adequate knowledge of Ind-AS on regular basis in preparation of quarterly/half yearly/ yearly financial statements as applicable (as per the requirement and intimation from HUDCO). Further, the qualified CA/CMA having adequate knowledge of Ind-AS shall attend the HUDCO for the said assignment minimum one day in a week during normal working days.
13. Any other services/assistance whatsoever required by HUDCO management relating to Ind-AS for preparation/finalization of financial statements.
14. The Ind AS Consultant firm will depute a Partner well versed with the subject to attend HUDCO Head-quarters at least once in fortnight and/or whenever required for the above consultancy assignments. The said representative shall interact with the concerned officials of General Account Wing at Head Office during visits as per HUDCO's requirement in Ind AS matters.
15. The Ind AS Consultant shall during the tenure of the contract and at any time thereafter keep all information relating to the work in full confidence and shall not, unless so authorized in writing by HUDCO, divulge or grant access to any information about the work or its results and shall prevent anyone becoming acquainted with either through consultant or its personnel or agents. Any monetary penalty/loss levied by any authority due to breach of the above clause will be the sole responsibility of the firm.
16. For execution of complete scope of work, the Ind AS Consultant will establish a team of qualified professionals as per the requirement of HUDCO. The Ind AS Consultant is solely and exclusively responsible for all the acts of its team members. The deputed professionals shall visit HUDCO on regular intervals for completion of all the assigned work, getting clarifications/ documents and also for rendering of advisory services as and when required by HUDCO.
17. At the end of every reporting period, Ind-AS consultant will issue a certificate before limited review report/audit report of that reporting period by Statutory Auditor of company in the format as suitable to the company/auditors from time to time.
18. Upon completion/ termination of this engagement all the data, information, material, records, documents copy other relevant papers available with the Ind AS Consultant shall become the sole and absolute property of HUDCO, and shall be returned by the Ind AS Consultant to HUDCO within 15 days of the termination of the contract.

CHAPTER 4: TECHNICAL CRITERIA & FORMAT FOR SUBMISSION OF BID

S. No.	Conditions	Documents Required	Annexure No.
1.	Valid address proof of the firm. The Firm should have its Head Office in NCR.	Certificate of firm from ICAI website duly signed by authorized signatory.	Annexure-1
2.	The CA Firm must have at least Five Partners as on the date of submission of tender.		
3.	As on the date of tender, minimum paid CA staff strength of the firm should be 10 employees (excluding partners and articled assistants).		
4.	At least 3 Partners of the Firm should have an experience of practicing as CA for more than 15 years.		
5.	Brief detail of qualified professionals (Partners and paid CA staff) employed by the bidder organization along with complete detail of members proposed for HUDCO assignment including their name, experience, profile, specialization etc. keeping in view the work of scope.	Full details on firm's letter head and member card of that partner of ICAI.	Annexure-2
6.	GST No.	GST Registration Certificate	Annexure-3
7.	CA Firm should have an experience of at least five years in Ind-AS consultancy of PSU's, out of which at least two years' experience in Ind-AS consultancy of NBFC's.	The copy of work-order along with satisfactory completion certificate to be enclosed.	Annexure-4
8.	The bidder should declare whether any partner/employee of the firm/company has any relation with any employee working in HUDCO, and, if so give the name of the employee and the relationship, and also whether any of them has a relationship within the meaning of Section 2(77) of the new Companies Act 2013, with any of the Directors of HUDCO, and also with the Statutory Auditors (M/s APRA & Associates LLP) and Internal Auditors (M/s Ravi Rajan & Co LLP) of HUDCO, if so give details to ensure compliance under sec 184 &188 of New Companies Act, 2013.	Certificate on letter head of the firm.	Annexure-5

9.	List of assignments carrying out at Corporate/ Regional Office of HUDCO.	The copy of work-order to be enclosed.	Annexure-6
10.	In addition to the above, the bidder should not have any of the disqualifications mentioned below: - a. There has not been any disciplinary action initiated by ICAI or any regulatory authority against the firm during last five years. b. None of the partners / employees has been convicted of any offence / economic offence. c. No appeal/unresolved dispute/suit/ case is pending at any court in India regarding the right to carry on practice.	Undertaking for the same on letter head of the firm.	Annexure-7
11.	The average annual turnover of the firm for the last three years should be ₹ 2 crores.	Chartered Accountant's certificate for FY 2018-19, 2019-20 & 2020-21.	Annexure-8
12.	EMD details.	(i) UTR No. and date (ii) Bank Name (iii) Amount Or MSME Certificate	Annexure-9
13.	The Ind AS consultant is required to certify that it will not indulge in any fraudulent activity or allow anybody else working in our organization to indulge in fraudulent activities and would immediately apprise HUDCO of the fraud/ suspected fraud as soon as it comes to their notice.	Certificate on letter head of the firm.	Annexure-10

Note:- All the bid documents should be signed by the authorized signatory of the firm. It should be noted that documents related to Internal audit, tax audit, stock audit or any other assignment which are other than IND-AS not required to be submit with bid.

Seal & Sign of Authorized Signatory

CHAPTER 5: Financial Bid Format

The financial proposal format (fees to be quoted both in words and figures): -

Particulars	Amount (Rs.)
Lump sum Quarterly professional fee (excluding applicable taxes) for rendering services mentioned in Scope of Work	
GST (18%)	
TOTAL	
Amount in words: -	

Seal & Sign of Authorized Signatory